

हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १९

सम्पादक : मगनभाई प्रभुवास देसाई

अंक १६

मुद्रक और प्रकाशक

जीवणजी डाह्याभाजी देसाजी

नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-१४

अहमदाबाद, शनिवार, ता० १८ जून, १९५५

वार्षिक मूल्य देशमें ६० ६
विदेशमें ६० ८; शि० १४

भूदानमें साध्य और साधन

अहिसक समाज-योजनामें हमें साध्य और साधनोंके स्पष्टीकरणमें हमेशा बड़ी सावधानी रखनी चाहिये। साध्यका थोड़ा भी अनुचित आग्रह हुआ कि उससे आसक्ति पैदा होगी और आसक्ति पैदा हुयी तो हिंसा भी जागेगी। चूंकि भूदान-आन्दोलन सर्वोदय समाजकी स्थापनाके लिये किया जा रहा प्रयत्न है जिसलिये हमें उसके उत्पादक अवयवोंको बहुत सावधानीके साथ समझ लेना चाहिये, उसके साध्यों और साधनोंका विश्लेषण करना चाहिये और उनके प्रति अपने मनोभावके बारेमें खूब सचेत रहना चाहिये।

भूदानके साध्यों और साधनोंका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है:

(१) आर्थिक — साध्य : गरीबीका निवारण
साधन : जमीनका समुचित उपयोग और उत्पादन

(२) सामाजिक — साध्य : मालिकीका हक समाजको सौंपना
साधन : जमीनका पुनर्वितरण

(३) राजनीतिक — साध्य : जमीनका शांतिपूर्ण हस्तांतरण
साधन : विचार-प्रचारके जरिये लोगोंकी दृष्टि और उनके हृदयका परिवर्तन

साध्यमें स्पष्टताकी आवश्यकता है और साधनोंमें पवित्रताकी। जब तक हम समुचित साधनोंका उपयोग करते रहेंगे, तब तक साध्योंमें गड़बड़ नहीं होगी।

जिसलिये यहां हम अपना सारा विचार साधनों पर ही केन्द्रित करेंगे।

१. गरीबीका निवारण जमीनका समुचित उपयोग करके ही किया जा सकता है। जब हम निर्यात या मिलोंके लिये उत्पादन करने लगते हैं, तो हम बेकारी पैदा करते हैं और गरीबी तथा कष्टकी वृद्धि करते हैं। जिसलिये हमें स्वावलंबन और स्वयंपूर्णताकी दृष्टिसे स्थानीय उपयोगके लिये ही उत्पादन करना चाहिये। किसानों और कार्यकर्ताओंको इस कार्यक्रमके धीरेकी तालीम देनेके लिये हमें कृषि-विद्यालयों और प्रदर्शन-केन्द्रोंकी (demonstration centres) की तीव्र आवश्यकता है।

२. अभी खेतीकी जमीनके क्षेत्रमें वैयक्तिक मालिकीका नियम चलता है। जिसे हमें बदलना है। छोटी या बड़ी किसी भी तरहकी खानगी मालिकी होनी ही नहीं चाहिये। ज्यादा जमीनवालोंसे जमीन ली जाय और फिर वह छोटे-छोटे टुकड़ोंमें किसानोंको व्यक्तिशः बांट दी जाय, यह बात ठीक नहीं है। जमीन जमीन जोतनेवालोंको अकेले निश्चित

अधिकके लिये ही दी जानी चाहिये और जिस बातकी जांच होनी चाहिये कि अन्होंने कैसा काम किया। जिस कदमकी सफलताके लिये भी कृषि-विद्यालयोंके जरिये कार्यकर्ताओंको तालीम देना आवश्यक होगा।

३. विचार-प्रचारके जरिये हमें जमीनका हस्तान्तरण शान्तिपूर्वक कर सकना चाहिये। लोगोंको समझाने और उनके हृदयको प्रभावित करनेके लिये हमें कार्यकर्ताओंकी आवश्यकता है। जिस अुद्देश्यकी सिद्धिमें हमारा साधन हमारे तालीम पाये हुये कार्यकर्ता ही हैं। यहां भी कृषि-विद्यालयोंकी स्थापनाकी आवश्यकता महसूस होती है।

जिस संक्षिप्त विश्लेषणसे हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा सारा ध्यान कार्यकर्ताओं, उनकी तालीम और तैयारी पर केन्द्रित करना चाहिये। जिसके बजाय अगर हमने उसे समय और परिमाण पर केन्द्रित किया, यानी यह आग्रह रखा कि जितने समयमें जितना काम हो ही जाना चाहिये, तो उससे हिंसाकी प्रवृत्ति पैदा होगी। लक्ष्य निर्धारित करना हिंसात्मक आयोजनका अंग है।

चूंकि हमारे कार्यका साधन कार्यकर्ता ही हैं जिसलिये हमारी मुख्य समस्या अन्हें बूढ़नेकी है। मौजूदा संस्थाओंमें जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं अन्हें ही निकालकर भूदानके काममें नियुक्त कर दिया जाय, ऐसा नहीं होना चाहिये। वह हिंसा होगी।

जिस बातको स्पष्ट करनेके लिये मैं एक-दो बड़े अुदाहरण देता हूं कि किस तरह भावनाके आवेगमें कार्यकर्ताओंने अपना कर्तव्य कार्य — जिसमें वे नियुक्त थे — छोड़ दिया और भूदानको मौजूदा आवश्यकता मानकर उसमें लग गये। (मैं आशा करता हूं कि जिनके अुदाहरण में यहां दे रहा हूं, वे मुझे माफ कर देंगे।) जीवनदानकी मांग पर श्रीमती आशादेवी आर्यनायकम् तुरन्त ही सद्भावपूर्वक आगे आयीं और अन्होंने अपनी सेवार्यें भूदानको अर्पित कर दीं। प्रश्न यह है कि क्या उनका जीवन बुनियादी तालीमके लिये पहलेसे ही अर्पित नहीं था? नयी तालीम सर्वोदय-व्यवस्थाका ही अक अंग है। भूदान सर्वोदयके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओंसे संबंध रखता है और नयी तालीम भावी नागरिकोंके निर्माणमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक योगदान करती है। दोनोंमें कौनसा कार्य अधिक महत्त्वका है? बुनियादी तालीमको छोड़कर भूदानमें जाना निश्चय ही अक कदम पीछे हटने जैसा है। बाजबलकी भाषामें कहें तो "यह नियमके विरुद्ध है कि बच्चोंके हाथसे रोटी लेकर उसे कुत्तोंको डाल दिया जाय।" इसी तरह श्री शंकरराव देव और श्री अण्णासाहब सहस्रबुद्धे, जो कि सर्व-सेवा-संघमें महत्त्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे थे, अपनी जगह छोड़कर भूदानमें चले गये हैं। असा और भी कभी लोगोंने किया है।

लेकिन अिन कुछका जिक्र यह स्पष्ट करनेके लिये किया गया है कि हमारा साधनोंका—कार्यकर्ताओंका—संग्रह अँसा नहीं होना चाहिये जिससे सर्वोदयके दूसरे कार्योंको हानि पहुँचे।

गांधीजीने जब सत्याग्रहियोंकी आम मांग पेश की, तो अुन्होंने कचहरियाँ, कालेज, स्कूल आदि अुन सारी संस्थाओंको खाली कराया जो सर्वोदय व्यवस्थाके बाहर थीं। वे सर्वोदयके बाहर ही नहीं, अुसके खिलाफ भी थीं और अिसलिये अुन्हें कमजोर बनाना प्रगतिका कदम था। मैं आपको बताअुं कि प्रत्येक आन्दोलनके समय गांधीजी अुझे स्पष्ट सूचना देते थे कि मैं अपना काम न छोडूँ। “गिरफ्तार होनेकी कोशिश मत करो और न कोअी प्रगट विरोधका काम करो। अगर अपना मौजूदा काम ही तुम ठीक तरहसे करते रहोगे, तो वे तुन्हे गिरफ्तार करेंगे ही।” मैंने कभी कोअी प्रगट विरोध-कार्य नहीं किया और न गिरफ्तार होनेकी कोशिश की और फिर भी मैं सात बार जेल हो आया। अगर हमने सर्वोदयके अंतर्गत किसी भी कार्यक्रमको अपना जीवन समर्पण किया है, तो हम किसी भी हालतमें अुसे छोड नहीं सकते। लक्ष्य निर्धारित करनेसे अत्युत्साही व्यक्ति अँसा कर बैठते हैं। हम अिस लोभसे सावधान रहें।

सर्वोदयमें कुछ भी अँचा या नीचा नहीं है। वह भंगी-काम भी क्यों न हो, अगर अुसे सच्ची सर्वोदयी भावनासे किया जाय, तो वह दूसरे कामोंके समान ही महत्वपूर्ण है। जिस बातका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वह है अहिंसा। अुससे ज्यादा जरूरी और कोअी चीज नहीं है।

(अंग्रेजीसे)

अ० सी० कुमारप्पा

जगतमें शांति कैसे हो ?

[ता० २४-४-५५ को ओडगां (अुत्कल) में दिये गये प्रार्थना-प्रवचनसे।]

आज आप देखते हैं कि अुघर बांडुगमें परिषद् चल रही है। दुनियाके आघेसे ज्यादा राष्ट्रोंके प्रतिनिधि वहां अिकट्टे हुअे हैं, और वे चाहते हैं कि दुनियामें शांति हो और दुनियाके लोगोंको युद्धमें न डकेला जाय, अिसलिये अपना नैतिक बल खर्च करें। वहां पंडित नेहरूने जाहिर किया कि चाहे दुनियामें लड़ायी चले तो भी हिन्दुस्तान अुसमें हिस्सा नहीं लेगा, अपने देशकी रक्षा अवश्य करेगा और युद्धमें भाग नहीं लेगा। और यह कहते हुअे अुन्होंने बताया कि मैं तो किसी बमके आघार पर यह नहीं बोल रहा हूँ। मैं यह जो बोल रहा हूँ वह हिन्दुस्तानकी जनतामें मेरा जो विश्वास है अुसके आघार पर बोल रहा हूँ। दुनिया युद्धकी आगमें लिपट जाय तो भी हम अलग रहेंगे, हमारे देशकी आजादीकी रक्षा करेंगे, शांतिके लिये सतत कोशिश करेंगे।

यह प्रतिज्ञा तभी पूरी होगी जब हम नैतिक शक्ति पर आघार रखेंगे और नैतिक शक्ति पैदा करेंगे। हमको समझना होगा कि हम अगर लश्करकी शक्ति पर भरोसा रखेंगे तो वह शक्ति हिन्दुस्तानमें नहीं है और अगर हम नैतिक शक्ति पर विश्वास रखेंगे तो हिन्दुस्तानमें नैतिक शक्ति पैदा हो सकती है। हिन्दुस्तानके पीछे दस हजार सालका अितिहास है, जिस अितिहासमें हिन्दुस्तानकी जनताने और हिन्दुस्तानके महापुरुषोंने सतत शांतिके प्रयोग किये हैं।

आज सारे अेधियामें लोअ शांति चाहते हैं, सारी दुनियाके लोग शांति चाहते हैं। तो सारे अेधियामें और दुनियामें शांति फैलानेके लिये बुद्ध भगवान्का और महात्मा गांधीका संदेश काम दे सकता

है। महात्मा गांधी और बुद्ध भगवान् दोनों ही हिन्दुस्तानमें पैदा हुअे हैं। और अिन दोनोंकी वाणीमें ताकत कैसे आयी? वह ताकत अिसलिये आयी कि हिन्दुस्तान देशकी बनावट ही अहिंसामें हुअी है। और अपने सारे अितिहासमें हिन्दुस्तानने किसी देशको तकलीफ नहीं दी है।

लेकिन हम केवल हिंसक लड़ायीमें भाग नहीं लेंगे, अितना कहनेसे अहिंसाका बल नहीं बनता है। यह तो अभावात्मक बात हो गयी। अहिंसाके लिये कुछ न कुछ भावात्मक काम करना होगा। तभी हमारा अहिंसाका बल बढ़ेगा। हमें यह कहना होगा कि हमारे देशमें जो विषमता है आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रमें, अुस विषमताको अहिंसाकी शक्तिसे मिटाना होगा। यह प्रत्यक्ष भावरूप काम करना होगा, तभी अहिंसाकी शक्ति बढ़ेगी और दुनिया पर अुसका असर होगा। यही सोचिये कि आपके प्राअिम मिनिस्टर दुनिया भरमें घूमते हैं और शांति और अहिंसाकी बात दुनिया भरको सुनाते हैं। अुसके साथ-साथ वे अगर यह भी कह सकें कि हमारे देशकी सामाजिक और आर्थिक समस्या शांति और अहिंसासे हमने हल की है, तो अुनकी वाणीमें कितना बल आयेगा? तो अिस भूदान-यज्ञके साथ-साथ संपत्तिदान, श्रमदान अित्यादि जो जुड़े हैं अुन सब यज्ञोंमें और सर्वोदय विचारमें अिस तरह भावरूप नैतिक और अहिंसक शक्ति निर्माण करनेका माहा है। अिसलिये हिन्दुस्तानके जवानोंमें भूदानके लिये और सर्वोदयके लिये अत्यन्त आकर्षण पैदा हुआ है।

आज सबसे ज्यादा भयभीत अगर कोअी हैं तो अिन्न अिन्न राष्ट्रोंकी सरकारके प्रतिनिधि ज्यादासे ज्यादा भयभीत हैं। हम कहते हैं कि यह सब सरकारोंकी सरकार जो है जनता, अिसमें शक्ति है प्रेमकी, अहिंसाकी, शांतिकी, सहयोगकी। अुसको जगाअिये तो दुनिया भयसे मुक्ति पायेगी।

समझनेकी बात है कि भूमि सबके लिये है। वह खरीदनेकी और बिक्रीकी चीज नहीं है। और अुसकी मालकियत नहीं हो सकती। अिस वास्ते भूमि पर सबका अधिकार है और सब लोगोंको भूमिकी सेवा करनेका मौका मिलना चाहिये। जैसे हवा, जैसे पानी, जैसे सूरजकी रोशनी सबके लिये है, वैसे भूमि भी सबके लिये है। यह बात सबको प्रेमसे समझानी है। हमारी वाणीमें कटुता नहीं होनी चाहिये, नअत्रता होनी चाहिये।

हमारे कुछ भाअी डर गये हैं कि न मालूम कानून कैसा होगा, क्या होगा? अिसलिये हिन्दुस्तानमें आजकल बेदखलियाँ आरंभ हुअी हैं। हम नहीं समझते कि जिन्होंने बेदखली की है वे कठोर-हृदय होंगे। हम समझते हैं कि अुनके हृदयमें डर पैदा हुआ है, निर्भयता नहीं है, अविश्वास है। अिसलिये वे डरसे गलत काम करते हैं। हमारा अुनसे भी प्रेम है और जो बेदखल हुअे हैं अुन पर तो हमारा प्रेम है ही। तो हम अुन लोगोंको समझाते हैं कि जिनको बेदखल किया है वे अगर भूमिहीन होते हैं, तो बेदखली की हुअी जमीन आप दान कर दें तो वह जमीन बेदखल हुओंको वापिस दी जायेगी। अुन किसानोंका नाम दानपत्र पर लिख दें—तो जो भयसे गलत काम हुआ है, वह दुरुस्त हो जायेगा और दान भी होगा और अुसके कारण समाजमें प्रेम-शक्ति बढ़ेगी। ये सारे हमारे भाअी हैं। जिनके पास कम जमीन है ज्यादा नहीं है, वे भी अगर कोअी गलत काम करें, तो अुन्हें हम दोष नहीं दे सकते, अुनका वेष नहीं कर सकते। हम प्रेमसे समझायेंगे तो वे समझ जायेंगे। भूदानके काममें बेदखलीको रोकनेका और अुन दोनों पक्षोंमें पड़नेका काम शामिल है।

विनीवा

२५०० वीं बुद्ध-जयंती

अगले साल बोधगयामें भगवान् बुद्धकी २५०० वीं (वैशाखी पूणिमा) जयन्ती ८ करोड़ रुपये खर्च करके मनायी जायगी। यह दिन बुद्ध भगवान्का जन्मदिन, बोधि-दिन तथा निर्वाण-दिन भी माना जाता है। यह अंक सुन्दर चीज है।

अगले साल इस दिन बड़ा आन्तरराष्ट्रीय समारोह होगा, जिसमें मुख्यतः बौद्ध राष्ट्र शामिल होंगे।

इस निमित्तसे मुख्य चार बौद्ध धर्मोंका जीर्णोद्धार होगा — लुंबिनी (जन्मस्थान), बुद्धगया (बोधस्थान), सारनाथ (प्रथम उपदेश स्थान) तथा कुशिनारा (निर्वाण स्थान)। महाजयन्ती गयामें मनायी जायगी। उसका स्थान वही रखनेका निश्चय किया गया है, जहां पिछले साल सर्वोदय सम्मेलन हुआ था। उसीके पास विनोबाजी द्वारा स्थापित समन्वयाश्रम भी है।

समन्वयाश्रम शांकर और बौद्ध तत्त्वोंकी समन्वित या परिपूर्ण फिलसूफी विचारनेके लिये स्थापित किया गया है। बौद्ध परिषदके कारण इस विचारकी अधिक छानबीन होगी असा हम मानें। दूसरी तरह भी आज यह वस्तु चर्चाका विषय बनी हुयी है।

बौद्धधर्मका जन्म भारतमें हुआ, लेकिन उसका विकास भारतसे बाहर हुआ और वहीं वह टिका। शंकराचार्यके युगसे उसका अन्त हो गया। लेकिन इससे भारतने बौद्ध सन्देशको छोड़ नहीं दिया। अनेक दृष्टियों और साधनाओंके सम्मेलन-रूप हिन्दू धर्मने उसे अपनेमें समा लिया था। अब जगत फिरसे अनुभवके परिणाम-स्वरूप अहिंसाको याद करता है, तब भारत उसके स्थूल केन्द्रोंके समान चार धर्मोंका जीर्णोद्धार करता है, यह खुशीकी बात है।

चीन, जापान, कंबोडिया, ब्रह्मदेश, लंका वगैरा देश राजनीतिके क्षेत्रमें भी भारतके साथी मित्र हैं, इससे इस महोत्सवकी सफलता और ज्यादा बढ़ जायगी। हम आशा रखें कि बुद्ध भगवान्के नाम पर मिलनेवाले ये सब राष्ट्र वैयक्तिक मारके निर्वाणके विषयमें ही नहीं, बल्कि युद्धरूपी महामारीके निर्वाणके विषयमें भी सोचेंगे और उसके भी आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग संसारको देंगे। इसमें भारतकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि उसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं।

श्री आम्बेडकर फिरसे बौद्ध बननेका मनोरथ पूरा करनेकी धमकी देते हैं। असा लगता है कि वे अगले साल इसके समारंभका आयोजन करना चाहते हैं। आजके इस युगमें जगत्का धर्म-विचार अतना विशाल और व्यापक बनता जा रहा है कि धर्म-परिवर्तन विचित्र वस्तु मालूम होती है। क्योंकि जिसे वास्तवमें धार्मिक बनना है, उसे अपना जन्मधर्म पूरा पूरा मार्गदर्शन प्रदान करता ही है। और उसमें सुधारकी हमेशा गुंजायिश रहती है। इसलिये श्री आम्बेडकरका यह कदम धर्मदृष्टिकी अपेक्षा दूसरी कोयी दृष्टि रखनेवाला मालूम होता है। यदि इसके पीछे हिन्दू समाजके प्रति वैरभाव काम कर रहा हो, तो यह धर्मान्तर धर्म्य नहीं माना जायगा। न उससे स्वयं आम्बेडकरको या दूसरे किसीको लाभ होगा।

यहां मुझे पूज्य कस्तूरबा और बापूजी याद आते हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र स्व० हरिलाल गांधी मुसलमान हुअे, तब अिन बुद्ध माता-पिताने अंक ही बात कही: असा करके भी हमारा यह पुत्र सचमुच 'हरिका लाल' बने तो वह भले अपनेको अब्दुल्ला कहे; इस शब्दका भी यही अर्थ होता है।

इसी तरह आज भारतका समाज श्री आम्बेडकरसे कह सकता है कि आप यदि असा करके भारतके बड़े और सच्चे सेवक हो सकते हों तो भले बौद्ध बन जायिये। परंतु यदि आपके

मनमें और कोयी भावना हो, तो जिससे बौद्धधर्मका या अन्य किसीका कल्याण नहीं होगा।

१८-५-५५
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

विश्वशांतिकी राजनीति

१९३८ में हिटलरने आस्ट्रिया हजम कर लिया। सामनेसे अंग्लैण्ड, अमेरिका, रूस, फ्रान्स वगैरा देशोंने उसे जकड़ लिया। इस तरह युद्ध तो रुका, परन्तु बादमें उसके विजेता आपसमें लड़ पड़े और उनका झगड़ा आज भी चल रहा है, जिसे अंग्रेजीवाले 'कोल्ड वार' या 'ठंडी लड़ाई' कहते हैं।

फिर भी अीश्वरकी कृपा है कि मंद गतिसे ही सही उनके सवाल अंक अंक करके हल होते जा रहे हैं। आस्ट्रिया हिटलरके पंजेसे छूटनेके बाद अपने छुड़ानेवाले राष्ट्रोंके हाथमें पड़ा। और अब वह उनके पंजेसे छूटकर स्वतंत्र हुआ है।

जर्मनी भी विजेता राष्ट्रोंके असे ही अधिकारका शिकार हुआ था। परन्तु उसके दो टुकड़े हुअे। अंक पर रूसने अधिकार जमा लिया, दूसरे पर अंग्लैण्ड-अमेरिका-फ्रान्सने। अिन तीनों देशोंने पश्चिम युरोपके कुछ राज्योंको मिलाकर 'नाटो' के नामसे पुकारा जानेवाला करार किया, जिससे अंक-दूसरेकी सहायता और रक्षा अच्छी तरह हो सके। अुन्होंने अपने हिस्सेके जर्मनीको स्वतंत्र बनाकर उसे शस्त्रसज्ज करके अुक्त 'नाटो' करारमें शामिल कर लिया है।

आस्ट्रियामें चारों पुराने मित्रराष्ट्र अंक होकर काम कर सके, लेकिन जर्मनीमें असा संभव नहीं हुआ। इसलिये रशियन या पूर्व जर्मनी अलग राष्ट्र है और वह सोवियट महामण्डलका अंक मनका बन रहा है।

दूसरे, पश्चिम जर्मनी सशस्त्र बनकर 'नाटो' करारमें शरीक हुआ, अिसे रूस बहुत खतरनाक और अपने खिलाफ अुठारा गया कदम मानता है। उसके जवाबमें अपने पक्षके युरोपके सात-आठ राष्ट्रोंकी मिलाकर रूसने अभी वासामें पूर्वोक्त 'नाटो' करारके खिलाफ दूसरा पूर्वीय 'नाटो' करार किया है! 'चर्चिलके कथनानुसार 'बल द्वारा शान्ति' बनाये रखनेकी युक्तिके व्यूहकी रचना इस तरह पूरी हो गयी है!

आस्ट्रिया स्वतंत्र हुआ उसमें अंक महत्त्वकी शर्त यह है कि स्विट्जरलैण्डकी तरह वह देश तटस्थ रहेगा। यह शर्त उस देशने भी स्वीकार की है।

रूस अब कहता है कि आस्ट्रियाकी तरह जर्मनीको भी तटस्थ राष्ट्र रखा जाय, तो मैं दोनों जर्मनीको अिकट्टा करके अंक स्वतंत्र तटस्थ राष्ट्र रचनेके लिये तैयार हूं। असा हो तो युरोपके पूर्वी और पश्चिमी प्रदेशोंके बीच तटस्थताकी दीवार खड़ी हो जायगी।

रूसको इस बातका बड़ा डर है कि जर्मनी सशस्त्र बनेगा तो वह फिर लड़ाईको जगायेगा। अमेरिका, अंग्लैण्ड वगैरा मित्र राष्ट्रोंको असा लगता है कि जर्मनी हमारे गुटमें सशस्त्र बनकर शामिल होता है तो हमें रूस विरोधी मोर्चा खड़ा करनेमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आस्ट्रियाका प्रश्न हल हो जानेके बाद अब जर्मनीकी अुलझी हुअी समस्या हल करनेका प्रश्न खड़ा होता है।

और रूसने अब 'युनो' के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि अणुशस्त्रों तथा अन्य सामान्य शस्त्रों पर नियंत्रण लगाया जाय और धीरे-धीरे उनका अन्त करनेकी बात सोची जाय। इसका क्रम भी अुसने बताया है। लेकिन इसमें बड़ी कठिनायी है परस्पर शंका और अविश्वाससे अुत्पन्न होनेवाले भयकी।

और ये दो पक्ष भारत जैसे तटस्थ तीसरे पक्षके बारेमें भी शंका करने लगते हैं कि हमारे बीच बेबनाव पैदा होने पर इस तीसरे पक्षकी तटस्थता कहीं टूट गयी तो क्या होगा?

जवाहरलालजीने बांडुंग सम्मेलनमें भारतकी भावी युद्धनीतिको स्पष्ट करते हुअे जोरदार शब्दोंमें कहा है कि भगवान् न करे कभी फिरसे विश्वयुद्ध हुआ तो भारत किसी भी हालतमें किसी पक्षके साथ शरीक नहीं होगा। तब खुद होकर किसी राष्ट्र पर अुसके आक्रमण करनेकी तो बात ही कहां रही? भारत विश्वकी शान्तिमें अिस तरह अपना योग देगा। गोआका हल हमारी अिस नीतिकी कसौटी करनेवाला होगा।

१९-५-५५
(गुजरातीसे)

मगनसाई देसाई

हरिजनसेवक

१८ जून

१९५५

हमारा सबसे बड़ा आधारभूत अुद्योग

पिछले माह पुरीमें हुअी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक कांफरेन्समें बोलते हुअे श्री खेरने हमारे देशमें होनेवाले शैक्षणिक सुधारकी स्थितिके बारेमें अेक मासिक विधान किया, जो भारतीय शिक्षा-पद्धतिके अेक भारी दोष पर हमारा ध्यान केन्द्रित करता है। श्री खेरने कहा:

“हमें अिस सत्यसे अिन्कार नहीं करना चाहिये कि ग्रामीण क्षेत्रोंकी प्राथमिक शालायें शहरोंकी प्राथमिक शालाओंसे भिन्न होंगी ही। आज तक हम अिस सत्यकी अपेक्षा करते रहे हैं, और शिक्षा-संबंधी हमारे सुधारोंकी कल्पना और रचना न केवल शहरी लोगों द्वारा की जाती है, बल्कि वह शहरी लोगोंके लिये ही होती है।” (मोटे टाअिप में किये हैं।)

शिक्षा-संबंधी सुधार करनेके हमारे तरीकोंमें शहरोंके पक्ष-पातका अूपर जो आरोप लगाया गया है, अुसका अुदाहरण हमें ताजीसे ताजी माध्यमिक शिक्षण कमीशन रिपोर्टमें भी देखनेको मिल सकता है। सीनियर प्राथमिक शालाओंमें अंग्रेजी भाषा सिखानेके प्रश्न पर अुसमें जो अनुदार या लगभग प्रतिगामी रुख प्रकट किया गया है, अुसकी चर्चा अिन कालमें पहले हो चुकी है। हमारे तथाकथित सुधारकोंका शहरों और शहरवासियोंके प्रति पक्षपात ही केवल अिस रूखका कारण था। दूसरा अुदाहरण बहुविध हेतुओंवाले (मल्टी-परपज) हाअीस्कूलोंके संबंधमें की गयी कमी-शनकी मुख्य सिफारिशसे दिया जा सकता है।

अिस सिफारिशमें विभिन्न प्रकारके विद्यार्थियोंके अनुकूल हो सकनेवाले वैकल्पिक पाठ्यक्रमोंकी कल्पना की गयी है। बड़े आश्चर्यकी बात है कि ये सारे पाठ्यक्रम मुख्यतः शहरी विद्यार्थियोंको काम देनेकी दृष्टिसे सोचे गये हैं। अुनमें वैकल्पिक अुद्योगोंके रूपमें ग्रामीण दस्तकारियां शामिल नहीं की गयी हैं, जो ग्रामीण हाअीस्कूलोंके लिये खास तौर पर बहुत ज्यादा अनुकूल हैं। हम जानते हैं कि हमारे देशकी योजनाबद्ध अर्थ-रचनामें ये ग्रामोद्योग कैसा महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण करते जा रहे हैं। अुनका स्वाभाविक गुण ही अितना मजबूर करनेवाला है कि देशके विद्वानोंका अुनके प्रति विवेकशून्य पूर्वग्रह होनेके बावजूद वे भारतके आर्थिक विचारमें अपना स्थान ले रहे हैं। अिसलिये निकट भविष्यमें ही देशको प्रेमे हज़ारों तालीम प्राप्त नौजवान स्त्री-पुरुषोंकी जरूरत होगी, जो गांवों और कस्बों वगैरामें खोजी जानेवाली सेवाओंमें काम कर सकें।

कम्प्युनिटी प्रोजेक्ट और नेशनल अैवस्टेन्शन सविस योजनाओंमें अभी तक ग्रामोद्योगोंको स्थान नहीं दिया गया था—यह अुन

थोड़ेसे शिक्षित लोगोंके शहरी पक्षपातका अेक दूसरा अुदाहरण है, जो आज योजना बनाते हैं, अुसका मार्गदर्शन करते हैं और अुसका संचालन करते हैं। खुशकिस्मतीसे अुन्होंने अब ग्रामोद्योगोंकी ओर ध्यान देना शुरू किया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना खादी-ग्रामोद्योग बोर्डके मातहत अिन अुद्योगोंको थोड़ा स्थान देना चाहती है। दुर्भाग्यसे आज हमारी यह स्थिति है कि हमारी शिक्षा-पद्धति अैसे काफी तालीम प्राप्त लोग नहीं निकालती, जो अिन नये परंतु सादे कामोंको भी हाथमें ले सकें। अगर हमने थोड़ी श्रद्धा और आवश्यक सहससे बुनियादी और अुत्तर-बुनियादी शिक्षाको कार्य-रूपमें परिणत किया होता तो आज परिस्थितियां विलकुल दूसरी होतीं। लेकिन जब जागे तभी सबेराके न्यायसे आज भी अिस दिशामें बहुत कुछ किया जा सकता है।

अगर हम शिक्षा-सुधारके शहरी पक्षपातके प्रश्न पर गहरा विचार करें, तो हमें पता चलेगा कि यह सचमुच केवल भौगोलिक वस्तु नहीं है; सच पूछा जाय तो यह अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति द्वारा पैदा किया हुआ हमारे समाजकी वर्ग-रचनाका भेद है। यह 'वर्ग बनाम आम लोग' का प्रश्न है।

भारतमें अंग्रेजी शिक्षाने अंग्रेजी जाननेवाले लोगोंका अैसा वर्ग खड़ा किया, जिन्होंने मुख्यतः देशके शासनकार्यमें ही अपनेको लगाया। विदेशी राज्यमें यहां जिस शिक्षा-पद्धतिका विकास हुआ, अुसने अंग्रेजी शासनकी यही जरूरत खास तौर पर पूरी की। अिसने कुछ दशकोंमें हमारी देशी शिक्षा-पद्धतिकी पूरी शकल ही बदल डाली। शैक्षणिक और सांस्कृतिक मूल्य बदलने लगे, जिन्होंने देशमें अेक अैसे मध्यम वर्गको जन्म दिया, जो नयी पद्धतिके मातहत काफी शिक्षा और तालीम प्राप्त होनेके कारण सरकारी नौकरियोंमें लगाया जा सके। जो शिक्षा देशकी संपूर्ण प्रजाके लिये होनी चाहिये थी, अुसने कुछ लोगोंको धंधोंके लिये तैयार करनेकी निरी तालीमका रूप ले लिया।

स्वभावतः अिस स्थितिसे हमारे शैक्षणिक और सांस्कृतिक मूल्य भी पूरी तरह बदल गये, अिसने शिक्षा-पद्धतिको वर्ग-शिक्षणका रूप दे दिया। अिस नयी व्यवस्था या परिवर्तित मूल्योंके दबावसे हमारी प्रजाकी मूलभूत शिक्षामें भी, जो युगोंसे लोगोंकी अपनी स्वशासित प्रवृत्तिके नाते काम कर रही थी, गड़बड़ी पैदा हो गयी। यह पद्धति जो ८० प्रतिशतसे ज्यादा लोगोंको साक्षर बनाती थी, अुलट गयी और हम अैसी दयनीय स्थितिमें आ पड़े, जिसमें ८० प्रतिशतसे अधिक लोग निरक्षर हैं और बाकीके लोगोंको अैसी तालीम मिलती है कि वे हमारे देशके नवनिर्माणमें सहायक होनेमें लगभग असमर्थ हैं। ये ८० प्रतिशत निरक्षर न केवल विदेशी शासकोंके लिये, बल्कि अुन्हें मदद करनेवाले देशके १० प्रतिशत अंग्रेजी शिक्षण प्राप्त किये हुअे लोगोंके लिये भी सख्त मेहनत-मशक्कत करनेवाले बन गये। बल्कि, जैसा कि राष्ट्रपतिजीने कुछ हफ्ते पहले कहा था, ये १० प्रतिशत शिक्षित लोग अब 'शिक्षित बेकारों' की संख्या बढ़ा रहे हैं।

ये पुरानी पड़ चुकी शिक्षा-पद्धतिकी अपज हैं, जो आज भी हमारे शैक्षणिक सुधार, शासन और तंत्र पर नियंत्रण रखते हैं। अिसका नतीजा जो होना चाहिये वही होता है, अर्थात् "हमारे शिक्षा-संबंधी सुधारोंकी कल्पना और रचना न केवल शहरी लोगों द्वारा (यानी अुन वर्गों द्वारा जो अब पुरानी पड़ रही और राष्ट्रविरोधी सिद्ध हो रही अंग्रेजी शिक्षण-पद्धतिकी अपज हैं) की जाती है, बल्कि वह शहरी लोगोंके लिये ही होती है।" जब तक हमारे लोग हिम्मतके साथ अिस स्थितिको सुधारनेकी चुनौती नहीं देते, तब तक किसी भी सच्ची लोकतांत्रिक योजनामें

ठोस या स्थायी प्रगति करना संभव नहीं होगा। जिस बातको याद रखना चाहिये कि शिक्षा किसी भी राष्ट्रका सबसे बड़ा जीवित बुद्योग है। उसका स्वरूप ही असा है कि वह भौतिक बड़े बुद्योगोंकी तरह मनुष्योंका अपुयोग कम करके मुख्यतः पैसे और यंत्रकी सहायतासे नहीं चलाया जा सकता। जिसमें मनुष्य प्रधान है, जो जीती-जागती जरूरतोंके अनुसार पैसैका अपुयोग करता है। दूसरी पंचवर्षीय योजनाको जिस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये — कमसे कम अतना तो देना ही चाहिये जितना कि तथाकथित बड़े या आधारभूत बुद्योगों पर दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा हमेशा किसी राष्ट्रका सबसे महत्त्वपूर्ण और सबसे आधारभूत बुद्योग होता है।

१२-६-५५
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

विविध विचार

जिस वर्ष सर्वत्र असंख्य शादियां हुयीं। खूब खाना-पीना हुआ, बाजे बजे और धूमधाम हुआ। पढ़नेवाले लड़कोंको जिसमें से अच्छी तरह उनका समाज-शिक्षण मिला। उनके पीछे लोगोंने करोड़ों रुपये खर्च किये। समाचारपत्रवालोंने पूनामें अकेले-दो दिनमें जो हजारों विवाह हुये और यज्ञोपवीत समारंभ हुये, उन्हें 'लगन-ज्वर' कहकर वर्णित किया। कहा जाता है कि शादियोंकी जिस बाढ़का कारण यह है कि आगामी वर्ष सिंहस्थ है।

हमारी संसदने भी अपने अनेक कामोंमें हिन्दू-विवाह, विवाह-विच्छेद, और अुत्तराधिकारसे सम्बन्धित कानूनों पर विचार किया। जिन्हें पास करनेमें असने भी अुतावली दिखायी।

जिन सुधारों पर विचार करते समय, चूँकि संसदके सम्य अूपरी या मध्यमवर्गके हैं जिसलिये उन्हें यह याद दिलाना पड़ा कि हिन्दुओंमें ८० प्रतिशतसे ज्यादा लोगोंमें — कानूनसे नहीं — जनशक्तिके आधार पर विवाह-विच्छेद आदि बातें जमानेसे चली आ रही हैं। अब जिन चीजोंकी अभी तक अपनेकी अुच्चवर्णी मानते आनेवाले लोग भी अपने लिये मांग करने लगे हैं। वे अितने 'सुधरे हुये' — या प्रगतिशील हैं कि इसके लिये अुन्हें कानून चाहिये! लेकिन जिस तरह वे ८० प्रतिशत लोगोंके साथ समानताकी विशामें बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है न? और अस हद तक जात-पातकी प्रथामें सुधार हो रहा है, यह तो कहा जायगा कि नहीं? अूँची और नीची जातियोंके बीचमें यह अेक बड़ा भेद तो अब नहीं रहा, असा कहा जा सकता है।

कानूनने अेक विवाह-पद्धतिका आदेश किया है। लेकिन जिसका यह मतलब नहीं कि राम-सीताकी तरह जीवनमें केवल अेक ही बार विवाह करना। कोअी जितनी बार चाहे विवाह कर सकता है, शर्त अितनी ही है कि अेकसाथ नहीं। पहले हिन्दू अेकसाथ अनेक विवाह कर सकते थे — (मुसलमान तो वसा धर्मबुद्धिसे कर सकते हैं, अुन्हें यह कानून लागू नहीं होता) अब अेक साथ नहीं कर सकते, अेकके बाद दूसरा, जिस तरह कर सकेंगे। बस अितना ही फर्क हुआ है। लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि जिन्हें 'अनेक विवाह' नहीं कहा जायगा। स्त्रियोंको भी यह अधिकार रहेगा।

और अेकके बाद दूसरा लगन करनेके लिये अेकके मरणसे घर-भंग होनेकी राह देखते बैठनेकी जरूरत नहीं है, अब तो आप कानूनकी मददसे अिच्छा होने पर घर-भंग कर सकते हैं। और यह नहीं भूलना है कि जिसमें 'सुधार' या प्रगति है। अरे, कितने युवक तो असे कानूनी घर-भंगका हक देनेवाली विवाह-पद्धति ही पसंद करते हैं। विवाहमें बंधनेके समय ही असे तोड़नेकी युक्ति सोच रखते हैं। घरमें घुसनेके पहले बाहर कूद भागनेकी खिड़की

देख रखना यंत्रशास्त्रकी दृष्टिसे भी सेफ्टी-वाल्कवा सच्चा सिद्धान्त है। जन्म और मरणके प्रति समान दृष्टि रखनेका वेदांत आज विवाहके मारफत भी बढ़ रहा है!

और विवाहकी पद्धतियोंमें भी नयी-नयी रीतियां चल निकली हैं। प्राचीन कालकी गांधर्व, राक्षस या पिशाच आदि नामोंसे प्रसिद्ध पद्धतियोंके नमूने फिर देखनेमें आने लगे हैं। लेकिन वह तो अेक बड़ी रामायण है। उसकी फिर कभी चर्चा करूंगा।

संक्षेपमें कहें तो आज अेक नयी स्मृति बन रही है; लेकिन किसी समर्थ स्मृतिकारके बिना ही। 'सत्यके प्रयोगों' की तरह 'नव-संसार' की रचनाके प्रयोग आज चल रहे हैं। लेकिन वे १०-१५ प्रतिशत पहले और अूँचे माने जायेवाले लोगोंमें ही। और जिस वर्गके लोगोंकी मनोदशा और विचारसृष्टि कितनी बेहाल है, यह तो भगवान् ही जानते हैं।

दाम्पत्यका आदर्श

पार्लियामेन्टमें विवाहके कानूनकी चर्चामें हिन्दू दाम्पत्य जीवनके आदर्शकी चर्चा भी हुयी। उसमें कहा गया कि विवाह अेक संस्कार है, करार नहीं। संस्कारमें शिक्षाकी, जीवन-विकासकी दृष्टि होती है; करारमें व्यापार है — सौदा है। जिसलिये अेकमें धर्मदृष्टि होनी चाहिये और दूसरेमें व्यवहार-दक्षता होनी चाहिये। सीताराम हिन्दुओंका दाम्पत्य-आदर्श है, और वह आदर्श आज भी बना हुआ है। तलाक द्वारा अैच्छिक गृहभंगकी हवा चल रही है, तब यह चीज याद रखनी चाहिये। उसमें अेक विवाह आजीवन व्रत बनता है। हिन्दुओंकी विवाह-पद्धतिमें यह सर्वोच्च शिखर जसा है। वह दृष्टिसे बाहर जायगा, तो हिन्दू समाजकी अूँची दृष्टि नहीं रहेगी। हिन्दू समाज अेक प्राचीन वयोवृद्ध समाज है। परन्तु वह जीर्णशीर्ण समाज नहीं — सनातन समाज है। क्योंकि देशकालके अनुसार होनेवाली बदला-बदलीमें भी वह अपने रामकी भूलता नहीं है। विवाह कानून जसा भी चाहें हम बनायें, परन्तु उसका केन्द्रबिन्दु असा भक्तिमें निहित है। यह चीज कानूनसे नहीं, परन्तु समाजके सच्चे धर्मपरायण जीवनसे ही सिद्ध हो सकती है।

नये जमानेका अर्थशास्त्र

हमारे अर्थमंत्री आज पूंजीके बहुत भूखे मालूम होते हैं। वैसे तो सारी ही सम्य दुनिया 'पूँजी पूँजी' पुकारती रहती है। सब कुछ बिलकुल पूँजीवादी बन गया है। किसान धान्य पाकर भी 'धन धन' करता रहता है और 'धान्य' से कभी तृप्त नहीं होता। मानो पूँजी अर्वाचीन मानवकी खुराक हो! कुछ लोग अिसे 'विटामिन अेम' (मनी) भी कहते हैं।

अर्थमंत्रीको सारे देशकी तरफसे भूख लगती है। विवाहोंके जिस भारी खर्चमें से वे कुछ नहीं छीन सकते? कानूनके मुताबिक विवाहोंकी नोंध करना शुरू हुआ है, जिसलिये अमुक फीस तो सरकारको मिलने लगी ही होगी। परन्तु क्या ज्यादा आमदनी नहीं की जा सकती? क्योंकि खर्चीली विकास-योजनाका लगन-मौसम सरकारने भी कोअी छोटा-मोटा शुरू नहीं किया है। और उसमें भी क्या लोगोंके विवाहोंके खर्च जसा धांधली नहीं मालूम होती?

विवाहमें जिमानेकी छूट मिल जानेसे जीमनेवालोंको तो आनन्द आ गया है। जीमनेका खर्च तो ठीक, लेकिन रोशनीका और ठाटबाटके दूसरे खर्च कितने बढ़ गये हैं! विवाहके मंडप मानो सिनेमामें देखे जानेवाले राजा-महाराजाओंके दरबार हों और बनाव-शृंगार करके आनेवाले स्त्री-पुरुष मानो सिनेमाके नट-नटी हों। क्योंकि आज तो हमारा शृंगार अुन नट-नटियोंको आदर्श मानकर चलता है न!

परन्तु जिससे क्या नये नये और सम्य धन्वोंको प्रोत्साहन नहीं मिलता? बेकार मध्यमवर्ग आसानीसे कमा सके, असे धन्धे नहीं बढ़ते?

कोयी कहेंगे कि आखिर इससे कितने धन्धे बढ़ेंगे? बात सच है, परन्तु इसी तरह यदि बिना धन्धेके धन्धे बढ़ाने लगे तो मायाके खेलकी तरह बिना धन्धेके धन्धोंकी बेकार सृष्टि काम नहीं देगी? यह नयी सम्यता इसके सिवा और भला क्या है?

परन्तु जैसे धन्धोंका खर्च कैसे निकले? यह सवाल भी अर्वाचीन अर्थशास्त्रका अज्ञान बताता है। सरकार नोट छाप कर समृद्धि बताती है; लोग मिलावट और चालाकी करके धन पैदा करते हैं तथा वकीलों द्वारा बुद्धिदान पाकर कर-चोरी करते हैं। (बिक्री-कर और आय-कर कानूनके अनुसार देना है, उसमें दान देने या किसी पर अपकार करनेकी बात नहीं है!) काला-वाजारका दाव भी चला नहीं गया है। 'परस्पर चोरयन्तः भूरि धनमवाप्स्यथ।'

परन्तु अन्तमें व्यंगको छोड़कर बात करूँ तो सनातन अर्थशास्त्र यह है कि देशका अंतिम भार तो प्रामाणिक श्रम और मानव-सदाचार पर ही रहता है। जिस धरती पर ही उस बिना धन्धेके धन्धोंकी भद्र सृष्टिकी माया खेल सकती है। यह भार अत्यधिक न बढ़ जाय, जिसका यदि देश ध्यान न रखे तो धरती डोलेगी — आजकी भाषामें क्रान्ति होगी। यह भी मानव-समाजका सनातन नियम है। क्योंकि 'धर्मो रक्षति रक्षितः' — मानव-रक्षाका यही मूल सिद्धान्त है।

१७-५-५५
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

शिक्षणकी जगह फौजी तालीम

भारत सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल नामक एक नयी संस्था खड़ी की है। ३० दिनके एक केम्पका आयोजन किया जायगा और उसमें १८ से ४० वर्षकी अग्र तकके पुरुषोंकी प्राथमिक फौजी तालीम दी जायगी। उसका हेतु यह बताया गया है कि यह प्रयोग देशकी आर्थिक और सामाजिक क्रान्तिका एक भाग है। उसके द्वारा लोगोंमें राष्ट्रीय सेवा, अनुशासन और स्वावलंबनकी भावना बढ़ानेका सोचा गया है। उसके पीछे कोयी फौजी हेतु या वैसी ही किसी अनिवार्य सेवाका खयाल नहीं है।

यह काम सेनाके लोग संभालेंगे। वस्तुतः यह चीज फौजी तालीमकी नहीं, समाज-शिक्षणकी है। इसके सिवा, अगर यह प्रयोग १८ से ४० वर्षकी अग्रवाले लोगों पर ही किया जायगा तो क्या वह पक्के घड़े पर किनारे चढ़ाने-जैसा ही व्यर्थ श्रम नहीं होगा? मौजूदा शिक्षण-पद्धति अनुशासन और सेवाका भाव प्रेरित नहीं करती, इसलिये यदि उसकी जगह इससे काम लेनेकी बात सोची गयी हो तो भी इसे व्यर्थ मानना होगा। कारण, धर्मकी तरह शिक्षणका स्थान भी कोयी दूसरी वस्तु नहीं ले सकती। शिक्षणको ही सुधारना चाहिये।

यहां सोचने जैसी बात यह है कि क्या अनुशासन और संयमके गुण फौजी तालीमसे ही आते हैं? यह तालीम अिन गुणोंकी शिक्षाके लिये है या युद्धके लिये? समाजमें अनुशासन और संयमके गुणोंका विकास करनेके लिये हरअेक प्रजामें धर्म-संस्था और शिक्षण-संस्थाकी रचना होती है। अिनके लिये युद्ध-संस्था होती है, अैसा तो सुननेमें कमी आया नहीं। और युद्धनिषेध तथा शान्तिके विचारोंके आजके युगमें युद्ध-संस्थाको अैसी प्रतिष्ठा देना भी दक्षताकी कमी सूचित करता है। बात यह है कि युद्धमें सफल होनेके लिये भी ये गुण जरूरी हैं। दूसरे नागरिक या मुल्की कामोंकी तरह अगर वहां ये गुण न हों तो काम नहीं चलता। सच पूछा जाय तो मुल्की काम भी अिन गुणोंके बिना नहीं चलते, इसीलिये तो आज लोगोंमें अनुशासन और संयमका भाव प्रेरित करनेके लिये अितनी मेहनत

की जा रही है। सेनाका तो वे आधार हैं; लेकिन वहां अिनके मूलमें स्वेच्छा नहीं रहती, इसलिये वह धंधेकी तालीम बन गयी है; उसमें शिक्षणका गुण और नागरिकताकी तालीमकी स्वेच्छा नहीं रहती। और सारे देशको सेना मानकर तो नहीं चला जा सकता; यद्यपि अैसा करना कुछ लोगोंको पसंद आता है, अैसा अहमदाबादमें अिस दलके वर्गका अुद्घाटन करते हुअे कहा गया! यह जानकर खुशी होती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक दलका अिरादा अैसा कुछ करनेका नहीं है।

तो नागरिकोंमें अिस गुणको प्रेरित करनेके लिये क्या करना अुचित होगा? पहली बात तो यह है कि शिक्षण-पद्धतिको ही विद्यार्थियोंमें अिन गुणोंका विकास करना चाहिये, जो कि बुनियादी तालीमका एक प्रधान व्येय है। दूसरे, अिन गुणोंकी सक्रिय तालीम समाजके चालू कामोंके मारफत दी जानी चाहिये। सारांश यह कि यदि समाजके सारे कामोंमें अनुशासन और संयमका पालन हो तो यह अुद्देश्य सिद्ध हो सकता है। इसलिये प्रजामें अिन गुणोंका विकास करनेका कारण मार्ग यह होगा कि सरकारी तथा सार्व-जनिक संस्थाओंके कामोंमें ही ये गुण प्रकट हों। आज तो अिस बातमें भारी कमी दिखायी देती है, जिसे दूर करनेकी जरूरत है।

अिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक दलमें आनेवालोंको जो प्रमाणपत्र मिलेंगे, वे हमारे देशके प्रचलित वातावरणमें यदि बिल्कोंका काम देनेवाले कागजके टुकड़े बनकर रह जायं तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि हमारे यहां अैसा ही होता आया है।

१७-५-५५
(गुजरातीसे)

मगनभाई देसाई

हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक संपत्ति

अमेरिकाके भूतपूर्व राजदूत श्री चार्ल्स बाबुल्सने भारतके योजनाकारोंके सामने एक बड़ा गंभीर प्रश्न रखा है। वह प्रश्न है: 'भारतकी सबसे बड़ी प्राकृतिक संपत्ति — अुसके नीजवान लोगोंका क्या किया जाय?'

हमारे योजनाकार आज केवल आर्थिक और पैसेसे संबंध रखने-वाली बातोंमें ही बहुत मशगूल हैं। यह स्वयंसिद्ध सत्य है कि किसी भी राष्ट्रके लिये भौतिक साधन-संपत्तिकी अपेक्षा नैतिक और मानसिक साधन-संपत्तिका हमेशा कहीं ज्यादा महत्व है। क्या हमारे योजनाकार अिसे भुला सकते हैं? वर्ना वे श्री बी० जी० खेर जैसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्तिको पुरीमें हुअी अ० भा० प्राथमिक शिक्षक परिषद्के द्वितीय अधिवेशनका अुद्घाटन करते हुअे वह प्रश्न पूछनेके लिये कैसे अुत्तेजित करते, जो अुन्होंने अिन शब्दोंमें पूछा है: "क्या ज्यादा साफ-सुथरे मकानों, ज्यादा चीड़ी सड़कों, पुलों और सिंचाअीके बांधोंसे अधिक बलवान, अधिक अच्छे और अधिक पवित्र मनुष्योंका कम मूल्य और कम महत्व है?" अुनका कहना था कि "हमारे धनका बहुत बड़ा भाग हमारे बालकोंको पाल-पोसकर और शिक्षा देकर आत्म-निर्भर, स्वाश्रयी और प्रामाणिक स्त्री-पुरुष बनानेमें खर्च किया जाना चाहिये।"

प्रश्न यह है कि अगर भारतके तरुण लोग बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षाके बिना बढ़ते हैं और अिसलिये नीचे गिरते हैं, तो दूसरी सारी अुभूति और प्रगतिका क्या अर्थ होगा और वह सब किसके लिये की जायगी?

अुस दिन दिल्लीमें प्रेस-कान्फरेन्सके सामने बोलते हुअे पंडित जवाहरलाल नेहरूने भारतके मानवोंके बारेमें कहा था, "प्रत्येक मानव एक अनिश्चित अिकाअी है और भारतमें अैसी ३६ करोड़ अनिश्चित अिकाअियां हैं!"

जनता राजनीतिज्ञ या अर्थशास्त्रीकी योजना या अमुक स्वरूपकी रचनाकी सामग्री नहीं है। बड़े दुःखकी बात है कि राष्ट्रीय कार्यके जिस पहलू पर कोभी ध्यान नहीं दिया जाता। श्री खेरने यह कह कर जिसकी अपेक्षाकी टीका की है, "हर राज्यकी अपनी नीति होती है या नहीं होती है और राष्ट्र कुछ समयके लिये जिन लोगोंके हाथमें सत्ता होती है उनके विचारोंके अनुसार ही आगे बढ़ता या पीछे जाता है।" जिसलिये उन्होंने जिस आवश्यकता पर जोर दिया कि "हमें अपनी राष्ट्रीय जरूरतोंके अनुकूल राष्ट्रीय शिक्षाकी पद्धति खोज निकालनी चाहिये।"

सारी योजना और समाज-व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षण-पद्धतिकी मजबूत बुनियाद पर ही खड़ी हो सकती है और अग्रगण्य कर सकती है। तब हम केवल अपनी भौतिक संपत्तिके बल पर ही काम नहीं करेंगे, बल्कि मानसिक और नैतिक संपत्तियां भी सही ढंगसे हमारे साथ सहयोग करेंगी। तभी योजना नीचेसे आम जनताकी प्रतिभा और बुद्धिके अनुसार आगे बढ़ेगी, न कि ऊपरसे देखने और संचालन करनेवाले योजनाकारों या सरकारके विचारोंके अनुसार, जो आम जनतासे अछूते रहकर आफिसके अंदर कंडी-शन्ड कमरोंमें बैठकर योजनायें गढ़ते रहते हैं।

३-६-५५
(अंग्रेजीसे)

मगनभाई देसाई

जनशक्तिसे ही सधेगा

राजस्थानसे अंक कार्यकर्ता लिखते हैं:

"२० मईसे २४ मई तक हम लोग भूदानमें प्राप्त भूमि-वितरणके लिये कोटडी तहसीलके गांवोंमें गये थे। ये गांव जागीरके थे। गांवोंमें जाने व वहांके लोगोंसे बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्थानमें जागीरें खत्म हो जानेके बावजूद गांववालों पर जागीरदारोंका आतंक ज्योंका त्यों है। काश्तकारोंको बेदखल किया जाता है तो गांववाले जागीरदारके खिलाफ शिकायत करने नहीं जाते और किसीने शिकायत करनेका साहस किया भी, तो जागीरदारके खिलाफ गांववाले गवाही देने नहीं जाते।

"अधर सरकारी कर्मचारियों (पटवारियों)का यह हाल है कि जब वे हलकेमें जाते हैं तो जागीरदारोंके यहीं ठहरते हैं। वहीं मुकाम लगाते हैं। रसोड़ेसे खाना आ जाता है। और आसामियोंको बुलानेकी भी जरूरत पड़ी, तो जागीरदारके दरवाजे पर ही बुलाया जाता है। दूसरे शब्दोंमें जागीरदारोंकी सत्ता समाप्त हो जाने पर भी ये लोग अपनी सुविधाकी दृष्टिसे अिन जागीरदारोंकी हुकूमतको जिस रूपमें बरकरार रखनेकी चेष्टा करते हैं। फलस्वरूप जागीरदार गांववालोंको दबाये रखनेकी सह पाते हैं। जिस तरह लोगोंको अिनके खिलाफ शिकायत करनेका साहस ही नहीं होता।

"होना तो यह चाहिये कि जहां कहीं भी बेदखलीकी या अन्य कोभी शिकायत मालूम हो, वहां पटवारी अुच्च अधिकारीकी जानकारीमें स्वयं ला दे, न कि यह अितजार करे कि कोभी फरियादी आवे तो कार्यवाही करे। फरियादी तो आज यह मान बैठा है कि अपनेसे शक्तिशाली व्यक्तिके खिलाफ फरियाद करना, अपने-आप पर आफत मील लेना है।"

और वे आशा करते हैं कि अधिकारी जिस पर ध्यान देंगे, तथा मुझसे पूछते हैं कि अखिर जिसका क्या हल है।

यह मसला पुराना है। अंग्रेजोंके राज्यकालसे चला आ रहा है। जिसके पहले हमारे हिन्दू या मुसलमान राज्यकालमें भी किसी न किसी रूपमें यह चालू था। आज हम जिसको न तो

पसंद करते, न चाहते हैं; क्योंकि हम प्रजाशासन या लोकशाही चाहते हैं।

पुराने ढंगमें सरकारी कर्मचारी, कम-ज्यादा अंशमें खुदको राज्यसत्ताधारी या सरकार ही मानता था। हमारी भाषा भी 'सरकार' कह कर कजियोंको पुकारती थी। यह अुस जमानेकी तसवीर थी।

जिस सत्ताके आधार पर सरकारी कर्मचारी मान, अिज्जत और दर्जा पाता था, अितना ही नहीं, भेंट-सौगात भी लेता था। और जिसमें शायद ही कोभी बुराही समझी जाती थी।

यह हाल अंग्रेजी राज्य-कालमें देहातोंमें तो बराबर बना रहा। अूपरके स्तरोंमें जिसने भले कुछ नया रूप पकड़ा ही। आज हम जिस हालतको पलटना चाहते हैं। जिसका अुपाय लोगोंके हाथमें ही है—हो सकता है। हां, स्वराज्य सरकार अमुक हद तक जिसमें मदद पहुंचा सकती है, जो पत्रलेखक चाहते हैं। यह मदद जरूर मिलनी चाहिये। वरना यह काम सही रूपमें तो अपने हकों और फर्जोंको समझनेवाली जनशक्तिसे ही होगा। भारतके नवनिर्माणमें यह अंक सबसे बड़ा और निहायत जरूरी काम है।

१३-६-५५

मगनभाई देसाई

दियासलाओका गृह-अुद्योग

भारत-सरकारने दियासलाओके गृह-अुद्योगके संगठन और विकासके लिये अ० भा० खादी और ग्रामोद्योग बोर्डको रु० ४,४३,८०० की रकम सौंपी है। यह अुद्योग नयी पैदा की हुअी 'घ' वर्गकी फैक्टरियोंकी श्रेणीमें आता है, जो रोजाना २५ ग्रास दियासलाओकी पेटियां तैयार करता है और जिसे चुंगीकरमें विशेष रिआयत दी गयी है, ताकि वह दियासलाओकी बड़ी फैक्टरियोंकी होड़में खड़ा रह सके।

सरकार द्वारा मंजूर की गयी रकममें से रु० १,००,००० का अुपयोग दियासलाओ बेचनेके लिये संगठित की गयी अुत्पादकोंकी सहकारी समितियोंकी कार्यकारी पूजी (वकिंग केपिटल)के तौर पर किया जायगा। और रु० २,२५,००० डेढ़ सौ सहकारी समितियों और दूसरी मान्य की हुअी संस्थाओंके बीच प्रति अिकाओी रु० १,५०० के हिसाबसे बांटे जायंगे, जो दियासलाओके अुत्पादनको संगठित करनेका काम करती हैं। बाकी बचे हुअे रु० १,१८,००० से लोगोंको तालीम देनेके कार्यक्रमोंका खर्च चलाया जायगा।

जिस वक्त कलकत्ताके पास सोदपुरके खादी प्रतिष्ठानमें तालीमकी सुविधा अुपलब्ध है, जो तालीम, शोध और अुत्पादनका केन्द्र है। तालीम डॉ० सतीशचन्द्र दासगुप्ताके सीधे मार्गदर्शनमें दी जाती है, जिन्होंने दियासलाओ अुत्पादनकी पद्धतियों और प्रक्रियाओंमें नये सुधार किये हैं। तालीमका पाठ्यक्रम ३ से ४ माहका है और अंक साथ ४० अुम्मीदवारोंको तालीम देनेकी सुविधा है।

जिस साल सोदपुर केन्द्र १२० अुम्मीदवारोंको बांसकी चिपटियोंसे दियासलाअियां बनाने और मंचवाक्सके लिये पेस्ट और कागजका अुपयोग करनेकी तालीम देनेकी आशा रखता है। चुने गये अुम्मीदवारोंको तीसरे दर्जेके आने-जानेके रेल-भाड़ेके अलावा विज्ञानके ग्रेज्युअेट हों तो ६० रुपये मासिक और दूसरे हों तो ४० रुपये मासिक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। आम तौर पर राज्योंके खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों द्वारा या दूसरी मान्य की हुअी संस्थाओं द्वारा भेजे गये अुम्मीदवारोंको ही भर्ती किया जाता है। लेकिन प्रवेशके लिये भेजी गयी दूसरे लोगोंकी अजियों पर भी विचार किया जायगा।

केन्द्रमें भर्ती करने और प्रत्येक पाठ्यक्रमकी तालीम देनेके लिये कोअी निश्चित समय नहीं रखा गया है। जैसे जैसे अजियां आयेंगी और अुम्मीदवारोंका चुनाव किया जायगा, वैसे वैसे अुन्हें भर्ती किया जायगा, ताकि तालीमका कार्य लगातार चलता रहे और दियासलाअीका गृह-अुद्योग शुरू करनेकी अिच्छा रखनेवालोंको अुनकी सुविधानुसार तालीम मिलती रहे। असलिये जो लोग दियासलाअी अुत्पादनकी तालीम लेना चाहते हैं, वे व्यवस्थापक, दियासलाअी गृह-अुद्योग, अ० भा० खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी प्रतिष्ठान, सोदपुर (कलकत्ताके पास) को विस्तृत जानकारीके लिये लिख सकते हैं।

अ० भा० खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, सी० के० नारायणस्वामी
आर्मी अेण्ड नेवी बिल्डिंग,
बम्बअी — १
(अंग्रेजीसे)

टिप्पणियां

बेकार मनुष्य और बेकार यंत्र

अभी कुछ दिन अुझे दो-अेक समाचार जाननेमें आये, जिन्हें सुनकर देशकी प्रजाको चिन्ता अुझे बिना नहीं रह सकती। पहली खबर यह आयी कि नदी-बांधकी योजनाओं पर होनेवाले खर्चके अनुमान फिर गलत मालूम अुझे हैं और अुनमें करोड़ों रुपयोंकी वृद्धि आवश्यक होगी। यह वृद्धि ५-१० प्रतिशत नहीं, ३०-४० प्रतिशतसे भी अुपर है। अनुमानमें कभी कभी नहीं, हमेशा वृद्धि ही निकला करे और वह भी अितनी ज्यादा, तो अिसे क्या कहा जाय? अिससे तो मालूम होता है कि अिन कामोंको योजना कहनेमें कोअी अर्थ नहीं, अंदाज भी नहीं कह सकते। 'लाखोंके लेन-देन' की बात कही जाती है, लेकिन यहां तो 'करोड़ोंका अन्दाज' कृता गया है।

दूसरी खबर यह मिली है कि अेक सरकारी समितिने कुछ बांध-योजनाओंका अुनके स्थान पर जाकर निरीक्षण किया तो यह मालूम अुजा कि ४८% यंत्र बेकार पड़े अुझे हैं; कारण अुन यंत्रोंके कुछ भाग, जो कम पड़ते हैं, अप्राप्य हैं। यह कैफियत तो अुन जगहोंकी है जहां समिति गयी थी। परन्तु जिन अनेक स्थानोंमें वह नहीं गयी, वहां क्या हो रहा होगा वह राम जानै। यंत्र लाये गये, अिससे मनुष्य-बल बेकार बना; अब यंत्र बेकार पड़े हैं तो सवाल यह अुठता है कि अुनमें पैसा लगानेका क्या अर्थ रहा? क्या अिसका कारण आवश्यकतासे ज्यादा अुतावली और अुसके फलस्वरूप योजनाके काममें धांधली पैदा होना नहीं है? कमेटी कहती है कि अिन नये यंत्रोंसे काम लेना हमारे अिजीनियरोंको अभी आता नहीं है। तो ये यंत्र मंगवाये क्यों और अैसी योजनायें बनायीं क्यों? सरकारके जवाबदार आदमियोंको यह सब देख-समझकर कामकी गति अिस तरह नियंत्रित कर देनी चाहिये जो चल सके। और छोटे अंदाज नहीं चलने देना चाहिये। यह सब देखकर अैसा लगता है कि सारे देशमें यदि अिन बड़ी-बड़ी योजनाओंके बबले छोटे छोटे काम शुरू किये गये होते और यह पैसा बेकार यंत्रोंके बजाय अुनमें लगाया गया होता, तो कितना अच्छा होता। वैसा होता तो पैसा कम लगता, अमरीकी मददके जालमें न फंसना पड़ता और जितना पैसा हम बचाकर खर्च करते, वह सब अिन सावधानीसे चुने अुझे समझे-बूझे कामोंमें लगनेसे पूरी तरह फलप्रद सिद्ध होता। अुजा सो अुजा, अभी भी स्थिति सुधर जाय तो अच्छा।

१४-५-५५

(गुजरातीसे)

म० प्र०

दूषित पैसा

'टाइम्स ऑफ अिण्डिया' अपने ता० ८-६-५५ के अंकमें बंगलोरकी ७ जूनकी यह खबर देता है:

"मैसूर सरकारने शब्दव्यूह प्रतियोगिता पर नियंत्रण लगानेवाले प्रस्तावित कानूनके विषयमें केन्द्रीय सरकारको अपने विचार बता दिये हैं। . . . कानूनमंत्री श्री अे० जी० रामचन्द्ररावसे जब पूछा गया कि क्या वे शब्दव्यूहों पर प्रतिबन्ध लगानेके पक्षमें हैं, तो अुन्होंने अुत्तर दिया कि अिस सुझावको मान लिया जाय तो दूसरी कभी बातों पर, जिनमें घुड़दौड़ भी शामिल है, प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा।"

'यह जानकर खुशी होती है कि मंत्री महोदय अपने राज्यकी नीतियोंका विचार करनेमें युक्तिसंगत होनेका प्रयत्न करते हैं। प्रश्न यह है कि अिन अनुचित मानी अुसी बातों पर नियंत्रण या प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये या नहीं? लेकिन अिस विषयमें मंत्री महोदयके विचार जानना ज्यादा ठीक होगा। और अिस संबंधमें अुन्होंने अखबारी रिपोर्टके अनुसार अेक चौकानेवाली बात कही है। जैसा कि अुपरकी खबरके अन्तमें कहा गया है:

"अुन्होंने कहा कि 'अिन बुरी बातोंको कुछ समयके लिये हमें बरदाश्त करना होगा', ताकि अच्छे अुद्देश्योंके लिये पैसा प्राप्त किया जा सके।"

दूसरी बहुतसी बुरी बातें भी हैं जो 'अच्छे' (?) अुद्देश्योंकी सिद्धिमें लगाये जाने लायक दूषित पैसा देती हैं। क्या मंत्री महोदय यहां भी युक्तिसंगत बनेंगे? लेकिन हमें तो यह सिखाया गया है कि दूषित पैसा अपने-आपमें अितनी बुरी चीज है कि अुसे छोड़ देना ही कहीं अच्छा है। अिसलिये मंत्री महोदयके अिस सिद्धान्तसे सहमत होना कठिन है कि अैसी बुराअीसे भला परिणाम निकल सकता है, जो मनुष्य द्वारा जानबूझकर लालचके कारण चलने दी जाती है।

१२-६-५५

(अंग्रेजीसे)

म० प्र०

भावी भारतकी अेक तसवीर

[दूसरी आवृत्ति]

किशोरलाल मधालाल

कीमत १-०-०

डाकखर्च ०-५-०

नवजीवन प्रकाशन मग्वर, अहमदाबाद-१४

विषय-सूची	पृष्ठ
भूदानमें साध्य और साधन	जे० सी० कुमारप्पा १२१
जगतमें शांति कैसे हो?	विनोबा १२२
२५०० वीं बुद्ध-जयन्ती	मगनभाई देसाई १२३
विश्वशांतिकी राजनीति	मगनभाई देसाई १२३
हमारा सबसे बड़ा आधारभूत अुद्योग	मगनभाई देसाई १२४
विविध विचार	मगनभाई देसाई १२५
शिक्षणकी जगह फौजी तालीम	मगनभाई देसाई १२६
हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक संपत्ति	मगनभाई देसाई १२६
जनशक्तिसे ही सधेगा	मगनभाई देसाई १२७
दियासलाअीका गृह-अुद्योग	सी० के० नारायणस्वामी १२७
टिप्पणियां:	
बेकार मनुष्य और बेकार यंत्र	म० प्र० १२८
दूषित पैसा	म० प्र० १२८